प्रेस विज्ञप्ति **5 जनवरी, 2015**

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने आज मीडिया के समक्ष निम्नलिखित बयान जारी किया :-

''मोदी सरकार के मुनाफाखोरी 'धर्म' के कारण आम आदमी के 'अच्छे दिन' की आस धराशाही हो गई है। श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सवा सौ करोड़ देशवासियों को पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी न करके सरेआम धोखा देने पर उतर आई है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने भाजपा के सेवा के वायदे से प्रभावित होकर उन्हें सत्ता में लाने का काम किया था। अर्थव्यवस्था में सुधार, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी और वृद्धि दर में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी चौतरफा नाकामी को छुपाने के लिए भाजपा सरकार आम आदमी के हितों की कीमत पर अपने खजाने को भरने में जुटी हुई है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने की बजाय उन पर आबकारी एवं कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है।

ये वही भाजपा है, जो कभी महंगाई और डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का ठिकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ती थी। ये वही भाजपा है जो बेशर्मी एवं निर्लज्जता का आचरण करके अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व गिरावट का लाभ आम आदमी और किसानों तक नहीं पहुंचने दे रही।

श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को निम्ननिलिखित पांच सवालों के जवाब देश की जनता के सामने तत्काल रखने चाहिएं :-

1. 26 मई, 2014 को केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 110.55 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 56 डॉलर प्रति बैरल गिरावट आई है। अर्थात इन सवा सात महीनों में प्रति बैरल 54.55 डॉलर या यूं कहें कि 50 प्रतिशत की गिरावट आई।

इसके विपरित पेट्रोल ओर डीजल की कीमतों में क्रमश: 15.73 प्रतिशत और 11.38 प्रतिशत की कमी की गई है। यदि इसे डालर से रुपये में तबदील कर दिया जाए तो मोदी सरकार की निर्लज्ज मुनाफाखोरी और स्पष्ट होती है।

जरा नीचे देखिए

	मई-2014 में कीमत (रुपये प्रति लीटर में)	**मौजूदा कीमत (रुपये प्रति लीटर में)**	**कटौती (रुपये में)**	**कटौती (प्रतिशत में)**
पेट्रोल	**72/-**	**61.33**	**11.33**	**15.73 %**
डीजल	**57/-**	**50.51**	**06.49**	**11.38 %**

हम जानना चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश के किसानों व आम आदमी तक कच्चे तेल की कीमतों में आई अभूतपूर्व गिरावट का लाभ क्यों नहीं पहुंचने दे रही ?

2. मोदी सरकार का किसान-गरीब-आम आदमी विरोधी चेहरा इस तथ्य से भी जाहिर होता है कि उसने 2 नवंबर, 2014 से 1 जनवरी, 2015 के बीच विमान ईंधन की कीमतों में 21.24 प्रतिशत की कमी की है। 2 नवंबर, 2014 को विमान ईंधन की कीमत जहां 76,241 रुपये प्रति किलो लीटर (76.24 रुपये प्रति लीटर) थी, उसे अब घटाकर 52,422 रुपये प्रति किलो लीटर (52.42 रुपये प्रति लीटर) कर दिया है।

इससे बड़ी विड़ंबना क्या होगी कि मोदी सरकार ने जहां पेट्रोल की कीमतों में 15.73 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 11.38 प्रतिशत की कमी की है, वहीं विमान ईंधन की कीमतों में 31.24 प्रतिशत की कमी की है।

इससे भी दर्दनाक बात यह है कि देश का आम आदमी जहां प्रति लीटर पेट्रोल के लिए 61.33 रुपये देने को अभिशप्त है, वहीं विमान ईंधन 52.42 रुपये प्रति लीटर में उपलब्ध है।

क्या श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा देशवासियों के साथ हो रहे इस घोर अन्याय के कारण बताएगी, जहां स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर का ईंधन, विमान ईंधन से महंगा है?

3. छह महीने से कुछ अधिक समय में मोदी सरकार ने पेट्रो उत्पादों पर निम्न प्रकार से तीन बार आबकारी ड्यूटी बढ़ाई है :-

(क) 12 नवंबर, 2014 को पेट्रोल एवं डीजल पर 1.50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी
(ख) 2 दिसंबर, 2014 को पेट्रोल पर 2.25 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी
(ग) 1 जनवरी, 2015 को पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

इसके अतिरिक्त सरकार ने कच्चे तेल की कस्टम ड्यूटी 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी है।

चालू वित्त वर्ष में बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से ही सरकार को 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। कस्टम ड्यूटी से होने वाली आय इससे अलग होगी।

हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार आम आदमी और किसानों के हितों की अनदेखी करके मुनाफाखोरी में क्यों जुटी हुई है?

4. मोदी सरकार तेल कंपनियों में पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण के लिए नये उपाय क्यों नहीं लागू करती, जिससे चोरी-छुपे लोगों से अधिक दाम वसूल करने पर प्रभावी ढंग से अंकुश लग सके?

पेट्रोल एवं डीजल के दाम, कच्चे तेल के दाम, शुद्धिकरण लागत और कंपनियों के मुनाफे को जोड़कर पारदर्शी ढंग से क्यों नहीं निर्धारित किए जाते?

5. मोदी सरकार पेट्रोल एवं डीजल के दामों को अपने नियंत्रण से सही मायनों में पूर्णतया मुक्त क्यों नहीं करती? मौजूदा नीति के तहत जब कच्चे तेल के दामों में निरंतर गिरावट आ रही है तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उसी अनुपात में लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? जब दाम बढ़ेंगे तो बढ़ी हुई लागत आम आदमी पर फिर थोंप दी जाएगी।

देश के आम आदमी, किसान व कमेरे वर्ग के साथ यह धोखाधड़ी पर आधारित विरोधाभास क्यों थोंपा जा रहा है?''